साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 03-09 फरवरी 2025 वर्ष-10, अंक-42
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मप्र के 66 लाख से अधिक किसानों को अब मिल सकेगा तीन की जगह पांच लाख रुपये का लोन

बजट की सौगातः 50.65 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ मिले

अन्नदाता खुश

- आम बजट में खेती-किसानों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने उठाए कई कारगर कदम
- तुअर, उड़द, मसूर और कपास उत्पादक बढ़ाने के प्रयास का प्रदेश के किसानों को होगा लाभ
- प्रदेश में 65 लाख 83 हजार 726 किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। खेती लाभकारी बनेगी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ेगी।
- सरकार की घोषणा से मध्य प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों का होगा विकास।
- अब केंद्र सरकार ने दस हजार करोड़ रुपए के कोष को बनाना तय किया।

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए देश का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है। कुल अनुमानित बजट 50.65 लाख करोड़ का रहा है, जो बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2 लाख करोड़ रुपये अधिक है। केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे ज्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए अनुमानित 4.91 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय राशि 48.21 लाख करोड़ रुपये रखी गई थी। यानी पिछली बार की तुलना में कुल बजट में 2 लाख करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट नहीं बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास के लिए वित्तवर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इतनी ही रकम पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी तय की गई थी। इस बजट को सड़क, आवास, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर करने में खर्च किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट किसानों के सशक्तीकरण का माध्यम बनेगा। एक ओर जहां खेती में लागत लगाने के लिए किसानों को राशि की व्यवस्था करने किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा तो दलहन और कपास उत्पादक किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। उच्च पैदावार वाले बीज तैयार करने के साथ उसका प्रसार किया जाएगा। नई किस्में आएंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और खेती लाभकारी बनेगी मध्य प्रदेश में 65 लाख 83 हजार 726 किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। अभी इन्हें तीन लाख रुपये तक ऋण मिलता है। सहकारी बैंकों के माध्यम से सरकार बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराती है। इसका उपयोग खाद-बीज खेत तैयार करने से लेकर अन्य कार्यों में किया जाता है। अब ऋण की यह सीमा पांच लाख रुपये होगी यानी दो लाख रुपये अधिक मिलेंगे। निश्चित तौर पर इससे अधिक किसान सहकारिता की व्यवस्था से जुड़ेंगे। इससे खेती का लागत भी कम होगी। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने मिशन घोषित किया है। दरअसल, प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में लगातार तुअर और उड़द का क्षेत्र घट रहा है। लागत अधिक होने और अन्य उपज कही तुलना में उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान दलहन फसलों से दूर हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तुअर की बात करें तो वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.63 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।

» यही स्थिति उड़द की भी रही। इसका क्षेत्र 34 प्रतिशत घटा, जबकि, मसूर के क्षेत्र 5.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, संतोष की बात यह है कि उत्पादन अधिक प्रभावित नहीं हुआ।

» इस योजना में वर्तमान योजनाओं का अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंड वाले जिले शामिल किया जाएगा।

» ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक कार्य म में कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आएगी।

» इस योजना के पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल में शामिल कपास का क्षेत्र मालवांचल है।

» इसका क्षेत्र लगभग साढ़े छह लाख हजार हेक्टेयर और उत्पादन 9.17 लाख टन हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित मिशन का लाभ मालवा और निमाड़ के किसानों को मिलेगा।

कृषि के लिए बड़ी घोषणाएं

- बिहार में नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा
- स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी स्कीम की घोषणा.
- स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ तक लोन मिलेगा.
- खिलोना उद्योग में ग्लोबल हब बनेगा भारत.
- खिलौना के लिए राष्ट्रीय नीति बनेगी.
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा
- छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे

किसानों की आय बढ़ाने कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर फोकस

किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कृषि से संबद्ध क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। सब्जियों और फलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रदेश में भी किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सब्जियों का क्षेत्र 11.88 लाख से बढ़कर 12.19 लाख हेक्टेयर हो चुका है। उत्पादन भी 242.62 लाख टन पहुंच गया है। आलू, टमाटर और प्याज का उत्पादन बढ़ा है। इसी तरह फलों की खेती को देखा जाए तो यह साढ़े चार लाख हेक्टेयर है और उत्पादन लगभग सौ लाख टन हो गया है। प्रमुख फसलों में केला, आम और नारंगी है।

क्रियान्वयन पर ध्यान दें

बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए प्रविधानों पर पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल का कहना है कि योजनाएं तो पहले से भी हैं लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। दलहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम पहले भी लागू किए जा चुके हैं पर इसका वैसा लाभ किसानों को नहीं मिली, जिस मंशा के साथ ये प्रारंभ किए गए थे। यही स्थिति कपास को लेकर भी है। उद्यानिकी फसलें निश्चित तौर पर लाभदायक होती हैं लेकिन यह तब जब उचित मूल्य मिले।

किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा

अभी समस्या बाजार की है। इसके अभाव में बिचौलिए लाभ उठाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में भले ही ऋण लेने की सीमा तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है पर इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। इसके स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की गारंटी, प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि किसान जब उसे उचित मूल्य तब उपज बेच सके।

भोपाल/नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को देश का बजट-2025 लोकसभा में पेश किया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं बजट से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी।

मोदी 3.0 का निर्मला ने पेश किया संपूर्ण बजट

'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

» व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट स्थापित किया जाएगा।

» ऊभरते टियर-2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी।

» भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।

» एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा।

» सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

» पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का प्रस्ताव।

» सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव।

» प्रतिस्पर्धी समनवित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।

» जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव।

» 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।

» पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

मोबाइल, एलईडी टीवी, कपड़ा और ईवी होंगी सस्ती

राहत का बजट

» बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा

» कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं भी अब होगी सस्ती

बजट-2025-26

उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपए और 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

सस्ती होंगी दवाएं

सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की है। इससे कैंसर की दवाएं शामिल है। कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता

वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत करने की बात कही है। टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। इससे बैटरी और खनिज बेस प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी।

लेदर गुड्स भी सस्ते

सरकार ने बजट में ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लागू होगा।

गोल्ड और सिल्वर यथावत

2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।

बजट की मुख्य विशेषताएं

भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

वर्ष 2025-26 का बजट पीएम नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने का रोडमैप है। बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आयकर न लगाकर एक बड़े वर्ग को राहत दी है। बजट हर नागरिक के सपनों का बजट है। यह एपम मोदी के ज्ञान के मंत्र पर आधारित बजट है, जो गरीब कल्याण, युवा कल्याण, नारी शक्ति और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित है। इस बजट से मध्यप्रदेश जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्य को मदद मिलेगी। बजट से विकास की प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और समावेशी विकास मजबूत होगा। निजी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।

-जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। केंद्रीय बजट पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करना एक दूरदर्शी कदम है।

-राजेंद्र शुक्ल, उपमुख्यमंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस आम बजट में देश के गरीब, किसान, नौजवान, मध्यमवर्गीय परिवार, व्यापारी, पिछड़ा, महिला, श्रमिक समेत हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार का बजट 2025 में नए भारत का विजन व समृद्ध और डिजिटल भारत का आधार स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75000 सीटें बढ़ाने की घोषणा इस बजट में की गई है।

-वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

यह 2047 के भारत का बजट है। देश के चहुंमुखी विकास का बजट है। पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों का बजट है। किसान, महिला, युवा, गरीबों, मध्यम वर्ग का बजट है। नारी शक्ति और नौजवानों को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। रोज़गार के लिए स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट के प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश को केंद्र का पर्याप्त अंश मिला है। यह एमपी के विकास का भी बजट है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा एलान किया गया है।

-कृष्णा गौर, राज्यमंत्री

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

-अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

-सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

-भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

-स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।

-कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

-6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा।

-500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

-मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।

-सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

-शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा।

-इस स्कीम को बैंकों से संबंधित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

-सरकार मिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

-सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

-सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव।

-घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।

-बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।

टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी।

-चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

-अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी।

-बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फैलोशिप।

-भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

-बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा।

बजट में यह भी सब कुछ

इंजन के रूप में कृषि

सरकार राज्यों की भागीदारी से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि

राज्यों की भागीदारी से 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। पहले चरण में 100 कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

- सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय दलहनों में आत्म निर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी।
- केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।
- उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

बीज मिशन

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा। बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

मत्स्य उद्योग

सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी।

कपास उत्पादकता मिशन

कपास की खेती की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इंजन के रूप में एमएसएमई

सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश। कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।

क्रेडिट कार्ड

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

निधियों का कोष

विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

उद्यमियों के लिए योजना

पांच लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।

ज्ञान भारतम मिशन

शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपी विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।

निर्यात संवर्द्धन

एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

फुटवियर और लेदर

भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना।

शहरी चुनौती कोष

एक लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा मिशन

परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। 20 हजार करोड़ के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा।

पोत निर्माण

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचनासुसंगत मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में एमबीबीएस की 2 हजार से अधिक सीटें बढ़ेंगी

-कैंसर रोगियों को डे-केयर सेंटर और 36 दवाओं में छूट

-36 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क छूट, इलाज सस्ता

डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में अगले पांच वर्ष में 75 हजार सीटें बढ़ाने की बात कही गई है, जिनमें 10 हजार सीटें 2025-26 के सत्र में बढ़ेंगी। इन सीटों में मध्य प्रदेश की भी बड़ी भागीदारी रहेगी। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। अगले तीन वर्ष में 12 कॉलेज प्रारंभ होंगे, जिनमें राजगढ़, बुधनी, दमोह, सिंगरौली और श्योपुर अगले सत्र (2025-26) से ही प्रारंभ करने की पूरी तैयारी है। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। सत्र 2026-27 में मंडला, धार और छतरपुर और उसके बाद उज्जैन, छतरपुर, सीधी टीकमगढ़ जिले में कॉलेज खुलेंगे। इस तरह 12 कॉलेज में दो हजार से अधिक सीटें रहेंगी। इनके अतिरिक्त 14 जिलों में सार्वजनिक, निजी भागीदारी (पीपीपी) से मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रयास चल रहा है।

अस्पतालों में इसी वर्ष प्रारंभ होंगे डे-केयर

बजट में अगले तीन वर्ष में देश के सभी जिलों में डे-केयर सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इनमें 200 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। इसका बड़ा लाभ कैंसर रोगियों को होगा। प्रदेश के संभागीय मुख्यालय वाले सभी जिला अस्पतालों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। डे-केयर में कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी, ब्लड चढ़ाने की सुविधा रहेगी। उन्हें दिन-दिन के लिए भर्ती कर उपचार किया जाएगा। अभी प्रदेश के अस्पतालों में सिर्फ भोपाल एम्स में ऐसी सुविधा है।

36 दवाओं को सीमा शुल्क से छूट

इसी तरह से कैंसर की 36 दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने और 37 दवाओं को रोगी सहायता कार्य म के अंतर्गत लाने से प्रदेश के कैंसर रोगियों को भी लाभ मिलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष 40 हजार से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास को गति देने वाला है। यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाएं और मध्यमवर्गीय परिवारों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए है। यह बजट राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करेगा। यह बजट कृषि, उद्योग, निवेश, निर्यात, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाला है। मोदी सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है।

-वैभव पंवार, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि भाजपा के लोग देश को लूट और बेच रहे हैं। इससे पहले भी जब-जब मोदी बजट लाए हैं, देश निराश ही हुआ है। भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय हो गया है। लूटो और बेचो देश को वाली नीति पर काम हो रहा है। देश में सरकारें नहीं बच रही हैं, केवल चुनाव हो रहे हैं। विकास दर नीचे है, लेकिन भाषण ऊंचे स्तर पर हैं। उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। देश पर 270 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।

-जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

ये पूरा केंद्रीय बजट बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वहां कई विशेष पैकेज दिए गए। नीतीश कुमार के भरोसे भाजपा की सरकार चल रही है इसलिए उन पर ही मेहरबानी की गई है। प्रधानमंत्री शायद भूल गए हैं कि देश का बजट पूरे देश के लिए होता है। किसानों के एमएसपी, आवास योजना, एससी एसटी और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है, उनकी योजनाओं को लेकर कटौती की गई है। प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों के कारण प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हीं को आज भूल गए। ये देश का बजट है देश के हिसाब से होना चाहिए।

-उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय मध्यम वर्ग सहित देश के करोड़ों नागरिकों को लाभान्वित करने वाला है। यह लोक-कल्याणकारी निर्णय आम जन की जीवन शैली को समृद्ध करने के साथ ही उनके आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। समूचे मध्यम वर्ग को बधाई। आगामी पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, ग्रामीण सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाएगी। इस बजट का लाभ सबसे ज्यादा मप्र के किसानों को मिलेगा।

भरतलाल पांडेय, भाजपा नेता, मऊगंज

मिट्टी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या, बायोचार से हो सकता है समाधान

दुनिया के कई हिस्सों में डीडीटी के कारण मिट्टी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शोधकर्ताओं ने इस जहर से होने वाले पारिस्थितिक खतरों को प्रबंधित करने के लिए इसे बायोचार के साथ मिलाकर एक नई विधि तैयार की है। इसके लिए स्वीडन के चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक पेड़-पौधों वाली नर्सरी की प्रदूषित मिट्टी में बायोचार मिलाया, तो मिट्टी में केंचुओं द्वारा डीडीटी का अवशोषण आधा हो गया। यह तरीका उस जमीन पर कुछ फसलों को उगाने में सफल हो सकती है जिन्हें वर्तमान में पर्यावरणीय खतरों के कारण अनुपयोगी माना जाता है।

डाइक्लोरो-डाइफेनिल-ट्राइक्लोरोइथेन (डीडीटी) 1942 से उपयोग किया जा रहा एक कीटनाशक है। हालांकि इसे 50 से अधिक सालों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी दुनिया भर की मिट्टी में अपेक्षा से अधिक मात्रा में बना हुआ है। स्वीडन में कीटों को नियंत्रित करने के लिए 50 और 60 के दशक में इसका उपयोग कैसे किया गया था, इसका एक उदाहरण डीडीटी में कटिंग को डुबोना था, अक्सर डीडीटी को जमीन में फैलाना शामिल था।

डीडीटी एक अंत:स्रावी विघटनकारी पर्यावरणीय जहर है जिसे जानवरों और लोगों में कैंसर, हृदय रोग और प्रजनन समस्याओं जैसे स्वास्थ्य प्रभावों से जोड़ा गया है। क्योंकि यह बहुत धीरे-धीरे नष्ट होता है, यह जानवरों की खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है, इस प्रकार यह बड़े शिकारियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, साथ ही लोग भी इससे प्रभावित होने में शामिल हैं।

कृषि मिट्टी में स्थिर कार्बन में चारकोल की भूमिका

जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन वह शब्द है जिसका उपयोग हम उस जीवन का वर्णन करने के लिए करते हैं जो पहले आए थे, सभी जीव जो आए और चले गए और अब मिट्टी में आराम करते हैं। किसान कार्बन चक्र के साथ किस तरह बातचीत करते हैं और इसे हमारी मिट्टी में संग्रहीत करते हैं, यह सवाल न केवल जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने का एक हिस्सा है, बल्कि इसके लिए खुद को तैयार करना भी है। कार्बन फार्मिंग, शालीनता का विज्ञान है - यह प्रश्न कि मजबूत, अधिक पोषक तत्वों वाले घने खाद्य पदार्थों को कैसे बनाया जाए, जिससे तनाव का स्तर अधिक हो। जैसा कि खेती के संरक्षक और बायोचार विशेषज्ञ स्टीव बेंसेल कहते हैं, मूल जैविक खाद्य आंदोलन की पिनकल्स और प्रथाएं काबज्न चक्र को समझने के आसपास थीं।

यह सुझाव देने के लिए एक बड़ा निकाय है कि बायोचार मिट्टी में देशी कार्बन को स्थिर करते हुए काबज्न आधारित अन्य प्रथाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह उस चीज़ से आगे निकल जाता है जो मैंने और कई लोगों ने सोचा था, जो यह है कि बायोचार बायोमास में लगभग 50प्रतिशत कार्बन को पायरोलिसिस में बदल देता है, जो हजारों वर्षों तक मिट्टी में एक स्थिर कार्बन स्रोत के रूप में रह सकता है।

क्या होता है बायोचार ?

बायोचार - जो चारकोल के समान है, एक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है जिसका उत्पादन सस्ता है। यह दूषित पदार्थों को बांधकर अलग करता है और मिट्टी में मिलाए जाने पर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। यह जलवायु में हो रहे बदलाव को कम करने में भी उपयोगी है क्योंकि यह मिट्टी में कार्बन के लंबे समय तक भंडारण में अहम भूमिका निभा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मिट्टी में केंचुओं द्वारा अवशोषित डीडीटी की मात्रा में औसतन 50 प्रतिशत की कमी आई जब मिट्टी को बायोचार के साथ मिलाया गया था। यह दिखता है कि मिट्टी के जीवों के लिए डीडीटी की जैव उपलब्धता कम हो गई थी, जिसका अर्थ है कि मिट्टी कम विषाक्त हो गई थी, जानवरों की खाद्य श्रृंखला में जैव संचय के माध्यम से या पानी में रिसने से डीडीटी के फैलने का खतरा कम हो गया था। पर्यावरणीय खतरों में यह कमी, भूमि मालिकों को उस जमीन पर फिर से खेती शुरू करने में सक्षम बना सकती है जो वर्तमान में अनुपयोगी हो गई है। बड़ी मात्रा में दूषित मिट्टी का उपचार करना महंगा और कठिन है। एक आम समाधान मिट्टी को खोदना और फिर उसे खतरनाक कचरे के लिए लैंडफिल में ले जाना है, लेकिन इसका मतलब है कि अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी को नष्ट करना और बड़े दूषित क्षेत्रों के लिए यह समाधान उचित नहीं है।

बायोचार का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने का अनुमान

इस तरह बायोचार के साथ उपचार भूमि को बिना खेती या खराब होने के बजाय उपयोगी बना सकता है और भूमि मालिक और पयाज्वरण दोनों के लिए काफी किफायती भी है। उपचारित इलाके में उगाई जा सकने वाली फसलों के उदाहरण हैं चीड़ और स्प्रूस के पौधे, पशुओं के चारे के लिए घास या बायोएनर्जी फसलें जैसे विलो पेड़ (सैलिक्स)। बायोचार के साथ उपचार का मतलब है कि पौधे मिट्टी से कम डीडीटी ले सकते हैं, लेकिन उपचार के बिना भी वे बहुत कम जमा करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज दूषित भूमि को बिना उपयोग किए छोड़ने का कारण यह नहीं है कि फसलों के साथ स्वास्थ्य को खतरा होगा, बल्कि इसलिए है कि भूमि मालिक नियमन द्वारा डीडीटी के साथ पारिस्थितिक खतरों को हल करने के लिए बाध्य है। इस पर जांच और निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए, भूमि बिना उपयोग के रह जाती है। बायोचार मिट्टी में बहुत धीरे-धीरे नष्ट होता है और उम्मीद जताई गई है कि उपचार का प्रभाव लंबे समय यानी दशकों तक बना रह सकता है। शोध में कहा गया है शोधकताज़ विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई सालों तक क्षेत्र के नमूने लेना जारी रखेंगे। समानांतर में शोधकताज़ यह पता लगाएंगे कि प्रयोग को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि बड़ी मात्रा में खुदाई किए बिना मिट्टी में बायोचार मिलाया जा सके।

बायोचार की अपार संभावनाएं

प्रदूषित मिट्टी के उपचार के लिए बायोचार का उपयोग आज सामान्य नहीं है। जहां तक शोधकर्ताओं को पता है, इस विधि का परीक्षण स्वीडन में जंगली नर्सरियों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसी मिट्टी के प्रकार और जलवायु में पहले नहीं किया गया। विज्ञप्ति में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि मिट्टी में डीडीटी और विभिन्न अन्य प्रदूषकों, जैसे धातुओं और पॉलीएरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के स्थिरीकरण के लिए बायोचार का उपयोग करने में बहुत अच्छा है। इसलिए यह हम अपने प्रयोग में एक अच्छा प्रभाव देखने में सफल हुए हैं। मिट्टी एक अनमोल संसाधन है जिसका पुनर्जनन बहुत धीमी गति से होता है, एक सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। यूरोपीय संघ में, 60 से 70 प्रतिशत मिट्टी क्षरण के कारण अस्वस्थ मानी जाती है, जिसमें मिट्टी का प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। विज्ञप्ति के अनुसार, मिट्टी के प्रदूषण को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर सक्रिय काम चल रहा है। यूरोपीय आयोग के आगामी मृदा निगरानी कानून में भूमि प्रबंधन और दूषित क्षेत्रों के उपचार के लिए नए, सख्त नियम शामिल हैं, जहां मिट्टी के स्वास्थ्य पर विचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

शोध में कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने मिट्टी के स्वास्थ्य के कई अन्य पहलुओं का भी पता लगाया है, जैसे कि पोषक चक्र ण, जल चक्रण और कार्बन भंडारण जैसे मिट्टी के कायोज़ पर विभिन्न उपचार प्रभाव, सकारात्मक परिणामों के साथ, डीडीटी पर बायोचार के प्रभाव के अलावा भी हैं।

उनका क्षेत्र में प्रयोग एक सामान्य पद्धति का प्रदर्शन है जिसे उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य पर सामान्य उपचार के विकल्पों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया है। इसे चिकित्सकों और निर्णयकर्ताओं, जैसे कि भूस्वामियों के लिए भी सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

बजट खेती, फसलों और किसानों के लिए वरदानः कृषि मंत्री

संसद में पेश हुए बजट को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 140 करोड़ भारतीयों के लिए अभूतपूर्व, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निमाज़ण का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि और किसान कल्याण समेत ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर इन क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूणज़ प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट 2025 में समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखा गया है। यह एक दूरदर्शी बजट है। इसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटनः कृषि मंत्री शिवराज सिंह के अनुसार, बजट 2025 में ग्रामीण विकास के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 88 हजार 754 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। वहीं, मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटनः कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को पक्के घर की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2025 में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत रिकॉर्ड 54 हजार 832 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को बलः कृषि मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना जैसे महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के लिए इस बजट में रिकॉडज़ बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की योजनाः केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीण संपन्नता और रेजिलिएंस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस पहल के तहत आजीविका, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलानः उन्होंने बताया कि कृषि को मजबूत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बीज सुधार और कपास उत्पादन पर जोरः कृषि मंत्री के अनुसार बजट में राष्ट्रीय बीज मिशन की शुरुआत होने का एलान किया गया है, जिससे अधिक उत्पादक और जलवायु अनुकूल बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। भारत में कपास उत्पादन को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए नया मिशन शुरू किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता के प्रयासः कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से तुअर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इससे देश को दलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।

कृषि अवसंरचना और फसलों के बेहतर दाम पर जोर

कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ेगा। टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के दाम किसानों को उचित मिलें, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान कृषि मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड गठन के एलान का स्वागत किया है।

केंद्रीय बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने का दांव

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब व्यापक आर्थिक हालात अनिश्चितता की गिरफ्त में हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के कारणों को समझने एवं उन्हें दूर करने पर अपनी ताकत लगा दी है। उपभोग या खपत में कमी पर हाल में काफी चर्चा हुई है और इसे ही कमजोर वृद्धि दर के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है।आयकर में राहत देकर और शहरी दिक्कतों पर ध्यान देकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर ढांचे में बदलाव (एक लाख रुपये महीना कमाने वाले लोगों को अब आय कर नहीं देना होगा) से मध्य वगज़ की जेब में ठीक-ठाक रकम आ जाएगी। अधिक रकम बचने से लोगों का झुकाव खर्च करने की तरफ बढ़ेगा जिसे देखते हुए निजी क्षेत्र भी निवेश करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। हाल के वर्षों में बजट में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में काफी इजाफा हुआ है। हालांकि, सार्वजनिक व्यय पूर्व के स्तरों पर ही है मगर ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्रालय मानता है कि घरेलू मांग बढ़ाने के सीधे उपाय किए बिना काम नहीं चलेगा और वृद्धि दर में कमी का सिलसिला नहीं थमेगा।

सरकारी खजाने से जुड़े व्यापक आंकड़ों की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी कंपनी के वित्तीय नतीजों की। इसके बावजूद सरकार ने बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। व्यक्तिगत आयकर प्राप्तियों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है और कर रियायत के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की छूट दिए जाने के बावजूद इसमें आने वाले साल में 14 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में वास्तविक अर्थ में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3 प्रतिशत का इजाफा होगा जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बजट में दिया गया बड़ा संदेश यह है कि उपभोग बढ़ने के साथ ही आर्थिक वृद्धि पटरी पर आ जाएगी। हाल के वर्षों में व्यक्तिगत आय करों में शानदार बढ़ोतरी को देखते हुए ही वित्त मंत्रालय ने संभवतः मध्य वर्ग को कर में बड़ी रियायत देने की घोषणा की है। राजकोषीय स्थिति संभालने के मोर्चे पर सरकार ने दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे पहले तो सरकार ने राजस्व व्यय पर अंकुश लगाकर व्यय की गुणवत्ता में सुधार किया है। दूसरी अहम बात यह है कि सरकार ने राजकोषीय स्थिति पर अधिक पारदर्शिता और इसे मजबूत करने की अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। ये दोनों ही बातें बजट में दिख रही हैं। बस व्यक्तिगत आयकर की भविष्य की दिशा को लेकर थोड़ा अंतर जरूर आया है क्योंकि बजट में प्रस्तावित कर राहत लागू करने से सरकार का गुणा-भाग जरूर बदलेगा। पिछले साल राजस्व व्यय में कमी की गई थी और इसे अंजाम देने के लिए सरकार ने आवास सब्सिडी और जल जीवन जल कार्यक्रम पर व्यय घटा दिया था। इसके अलावा जुलाई 2024 के बजट में पूंजीगत व्यय के कुछ मदों में भी आवंटन काफी कम किए गए थे। सरकार के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इन अनुमानों की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का दीर्घकालिक रास्ता थोड़ा अस्पष्ट लग रहा है। बजट में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि सरकार भविष्य में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगी। इस बजट से जुड़ी राजनीति में भी पारदर्शिता दिखी जो असामान्य उपलब्धि मानी जा सकती है। सरकार ने कुछ राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं तो की हैं मगर उनसे सरकारी खजाने पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह बजट मध्य वर्ग के नाम रहा है और पूंजीगत व्यय जैसी चिंताओं को अधिक तवज्जो नहीं दी गई है। प्रत्यक्ष करों के तर्कसंगत बनाने के साथ कर सुधार की उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। अगर 2025 में आर्थिक वृद्धि पटरी पर लौट आई तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी।

बजट में कपास, मखाना, सब्जी और फल मिशन, दलहन मिशन और हाइब्रिड बीज मिशन की घोषणा

पीएम फसल बीमा का बजट 3 हजार करोड़ घटाया

नई योजनाओं से होगा कृषि विकास और किसान कल्याण पर सरकार का जोर

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए बीते वित्त वर्ष से 19 हजार करोड़ से अधिक रकम आवंटन का प्रावधान किया गया है। हालांकि, पीएम फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने बजट को घटा दिया है। जबकि, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए भी बजट नहीं बढ़ाया गया है। जबकि, कपास, मखाना, सब्जी और फल मिशन, दलहन मिशन और हाइब्रिड बीज मिशन की घोषणा की गई है और इनके लिए पहली बार अलग से रकम आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार पीएम फसल बीमा योजना के लिए रकम आवंटन को बढ़ाएगी, लेकिन इसके उलट सरकार ने बजट अलोकेशन को घटा दिया है। केंद्र ने बीते 3 वित्त वर्ष में हर साल फसल बीमा का अनुमानित बजट रकम को बढ़ाया है, लेकिन इस बार घटा दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने बजट 2023-24 में फसल बीमा के लिए 12949 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके बाद 2024-25 के लिए बजट एस्टीमेट 14600 करोड़ रुपये रखा गया, लेकिन बाद में इसे रिवाइज कर 15864 करोड़ रुपये बढ़ाया गया। इस बार केंद्र ने 2025-26 बजट एस्टीमेट में 12242 करोड़ रुपये रखा है। यह बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 3 हजार करोड़ कम है।

नहीं बढ़ा सम्मान निधि का बजट

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान कल्याण योजना पीएम किसान सम्मान निधि के लिए इस बजट में रकम आवंटन बढ़ाने की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 63500 करोड़ आवंटन का प्रावधान किया है। यह बीते वित्त वर्ष 2024-25 में 60000 करोड़ रुपये का एस्टीमेट रखा गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 63500 करोड़ किया गया था। इस बार भी बजट में किसान सम्मान निधि के लिए इतनी ही रकम आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। बजट से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी सम्मान निधि की सालाना किस्त 6 हजार रुपये से बढ़कर 8 हजार या 12 हजार रुपये हो जाएगी। हालांकि, आवंटित बजट को देखते हुए इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

नई कृषि योजनाओं को अलग से बजट मिला

वित्तमंत्री ने बजट में कृषि के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें कपास, मखाना, सब्जी और फल मिशन, दलहन मिशन और हाइब्रिड बीज मिशन शामिल हैं। इन सबके लिए अलग-अलग बजट राशि आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को 6 साल किया गया है और इसके लिए 1000 करोड़ राशि प्रस्तावित की गई है। कपास तकनीक मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मखाना बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपये और सब्जी फल मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हाइब्रिड बीज मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है।

कृषि योजनाओं के लिए कितना मिला पैसा

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट वित्त वर्ष 2024-25 के 6000 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार बढ़कर 8500 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।
- खाद सब्सिडी के लिए बजट वित्त वर्ष 2024-25 के 119001 करोड़ की तुलना में इस बार बजट 2025-26 के लिए 118900 करोड़ रकम आवंटन का प्रस्ताव है।
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की रकम बीते बजट वित्त वर्ष 2024-25 में 52310 करोड़ की तुलना में घटाकर इस बजट 2025-26 में 49000 करोड़ की गई है।
- कृष्णोन्नति योजना के लिए बीते बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि इस बार बजट बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये किया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का बजट बीते 2 वित्त वर्ष से समान है और इस बार भी 86000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।
- ग्राम जीवंत कार्यक्रम के तहत बजट 2025-26 के लिए रकम आवंटन 1056 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन के तहत 2 लाख से अधिक किसानों को लाभ

प्रदेश में किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए नित नवाचार कर रही है मोहन सरकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में कई नवाचार किऐ जा रहे हैं और उपलब्धियाँ हासिल हो रहीं हैं। वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 लाख से अधिक किसानों को लाभांवित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन अंतर्गत कृषकों को डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक राशि का लाभ प्रदान किया गया है। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 207 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट एवं 644 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 81 लाख कृषक आवेदनों का 41.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीमांकन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 25.79 लाख कृषकों को 755 करोड़ राशि के दावा भुगतान किये गये। किसानों को शीघ्रता से हरसंभव दावा भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बीज से संबंधित एक वर्ष की उपलब्धि- खरीफ 2024 में कुल 22.87 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का शासकीय, सहकारी एवं पंजीकृत निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से वितरण किया गया। प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्धता के लिये संभाग स्तर पर 10 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। वर्ष 2023-24 में 21920 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 17376 बीज नमूने लिये जाकर 14085 नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषित किये गये। जिसमें 12955 मानक तथा 1130 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 1070 विक्रय प्रतिबंधित, 186 लाइसेंस निलंबन तथा 70 लाईसेंस निरस्त किये गये। खरीफ 2024 में 13140 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 10235 नमूने लिये गये एवं 10212 विश्लेषित किये गये। जिसमें 9422 मानक तथा 790 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 534 विक्रय प्रतिबंधित, 25 लाइसेंस निलंबन तथा 8 लाईसेंस निरस्त किये गये।

ऑन ईडीबल ऑईल तिलहन

वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार 3629.05 लाख रूपये का आवंटन जिलों को जारी किया गया, जिसके विरुद्ध जिलों द्वारा 1991.45 लाख का व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 144.35 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1392 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषको को लाभान्वित किया गया। सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना में वर्ष 2023-24 में 141 लाख व्यय किए जाकर 4 नर्सरियों को लाभान्वित किया गया।

बलराम तालाब

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम तालाब योजना में कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण निर्माण पर सामान्य कृषकों को लागत राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 80 हजार, लघु सीमान्त कृषकों को लागत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि, 80 हजार तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख का अनुदान दिए जाने का प्रावधान निहित है। वर्ष 2023-24 में 569.30 लाख व्यय किये जाकर 662 बलराम तालाब निर्मित किये गये गये हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राशि 5308.34 रुपए का वित्तीय लक्ष्य एवं 6144 बलराम तालाब निर्मित किये जाने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

विविधीकरण

फसल विविधीकरण योजनान्तर्गत 6726 किसानों के साथ 4797 हेक्टेयर में विविधीकरण कार्य किया गया है एवं अभी तक लगभग 983.45 लाख रुपये का बायबैक किया गया है

राज्य सरकार ने पिछले साल से लिया सबक

मप्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का लक्ष्य 20 लाख टन घटाया

-प्रदेश में लगभग सौ लाख हेक्टेयर में हुई गेहूं की बोवनी

-गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2,425 रुपए

जागत गांव हमार, भोपाल।

प्रदेश सरकार हर बार की तरह इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। पिछले साल 100 लाख टन उपार्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसके हिसाब से ही बोरे, सिलाई के लिए धागा और भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से साख सीमा स्वीकृत कराई गई थी। सरकार ने ऋण की गारंटी ली, पर खरीदी 48 लाख टन ही हुई थी। इससे सबक लेते हुए सरकार ने इस बार लक्ष्य 20 लाख टन घटा दिया है। अब 80 लाख टन के हिसाब से तैयारी की जा रही है, जबकि गेहूं बोवनी का क्षेत्र चार लाख हेक्टेयर बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हो गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2,425 रुपये है। यह पिछले वर्ष 2,275 रुपये था। इस पर सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया था। छह लाख 16 हजार किसानों से 48 लाख 38 हजार टन गेहूं खरीदा गया जबकि, सरकार ने बारिश होने के कारण उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण चमकविहीन गेहूं के लिए निर्धारित मापदंड से छूट भी ले ली थी। दरअसल, उपज का दाम बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक था, जिसके कारण किसानों ने सरकार को देने के स्थान पर या तो बाजार में बेचा या फिर रोककर रख लिया। इसे देखते हुए सरकार ने आकलन किया और

इस बार के लिए उपार्जन का लक्ष्य सौ लाख टन के स्थान पर घटाकर 80 लाख टन कर दिया। गुणवत्तायुक्त खरीदी सुनिश्चित करने के लिए उपज ग्रेडिंग करके ली जाएगी। इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही किसानों को भुगतान उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सीधे किया जाएगा।

उपज बेचने में मदद करता है एमपी फार्म गेट ऐप

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि एमपी फार्म गेट मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है। यह किसानों को अपनी फसलों की बिक्री एवं बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। इस ऐप के माध्यम से किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। मंत्री कंषाना ने कहा है कि यह ऐप किसानों को उपज बेचने में सुरक्षित लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और एनआईसी एमपी द्वारा विकसित किया गया है। गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है।

ग्रीष्मकालीन (जायद) मूंग उत्पादन की उन्नत तकनीक

**डॉ. नरेन्द्र कुमावत
एवं डॉ. दीपिका चौरे**
अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना, कृषि महाविद्यालय, इंदौर
(राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविधालय, ग्वालियर, मप्र)

मूंग भारत में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें 24 प्रतिशत प्रोटीन के साथ-साथ रेशे एवं लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। मूंग दलहनी फसल होने के कारण राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा वायुमण्डलीय नत्रजन को मृदा में संचित करने की क्षमता रखती है। मूंग की जल्दी पकने वाली एवं उच्च तापमान को सहन करने वाली प्रजातियों के विकास के कारण जायद में मूंग की खेती लाभदायक सिद्ध हो रही है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही की जा सकती है। ग्रीष्मकालीन मौसम में मुंग की खेती कम लागत एवं अधिक उत्पादन लेने हेतु नि न उन्नत तकनीकी को अपना कर अधिक मुनाफा कमा सकते है ।

भूमि एवं खेत तैयारी- मूंग की खेती के लिए हल्की से भारी भूमि उपयुक्त रहती है। मूंग को रेतीली से काली कपास वाली सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है परंतु इसकी खेती के लिये अच्छे जलनिकास वाली दोमट मृदा सवोज्त्तम होती है। क्षारीय एवं अ लीय भूमि मूंग की खेती के लिये उपयुक्त नहीं होती है। जायद की फसल के लिये पलेवा देकर खेत की तैयारी करनी चाहिये। 2-3 जुताई देशी हल से करने के बाद पाटा लगाना चाहिये जिससे मृदा भुरभुरी हो जाये और भूमि में नमी संरक्षित रहे।

उन्नत किस्में

एस एम एल 668 - यह किस्म जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में से एक हैं। इसकी फलियां नीचे की ओर गुच्छे के रूप में झुकी होती हैं। इस किस्म के दाने मोटे होते हैं। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 12-15 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

मोहिनी - मूंग की मोहनी किस्म 70-75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी हर फली में 10-12 बीज और दाने छोटे होते हैं। मूंग इस किस्म में पीला मोजैक वायरस को सहन करने की क्षमता होती है। यह किस्म 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है ।

एम.यू.एम 2 - मूंग की इस किस्म का पौधा करीब 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इस किस्म के दाने का आकार में मध्यम और चमकदार लगते हैं। मूंग की ये किस्म 80-85 दिन में पक जाती है प्रति और हेक्टेयर 15-18 क्विंटल पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

पूसा विशाल यह किस्म 70-75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसको जायद और खरीफ मौसम में उगाया जा सकता है। इससे प्रति हेक्टेयर 15-20 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकती है।

पंत मूंग 1 - मूंग की यह उन्नत किस्म 75 दिन में पक कर तैयार होती है। इसके अलावा जायद के मौसम में फ़सल को 65 दिन में पक सकती है। इसके दाने छोटे होते हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 10-12 क्विंटल पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

मूंग कल्याणी - इस किस्म की फली लंबी गुच्छों में होती है और इसका दाना मोटा और गहरे हरे रंग का चमकदार होता है। मूंग की इस किस्म से प्रति एकड़ उत्पादन 6-7 क्विंटल पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ये किस्म पीला मोजेक, चूणिज्त आसिता रोग के प्रति सहनशील है।

पी.एस. 16 - यह किस्म लगाने से फ़सल 60-65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका पौधा सीधा और लंबा बढ़ता है। इसके पैदावार की क्षमता प्रति हेक्टेयर 10-15 क्विंटल तक होती है। मूंग की यह किस्म बारिश और ग्रीष्म, दोनों मौसम में उपयुक्त मानी गई है।

मुंग की अन्य किस्में : के. 851, पूसा वैशाली, आरएमजी 62, एम.यू.एस. 2, पूसा बैशाखी, आई.पी.एम. 205-7 (विराट), एम.एच. 421, आई.पी.एम, 410-3 (शिखा), पी.डी.एम. 139 (सम्राट) आदि ।

बीजदर एवं बीजोपचार

ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हेतु 15-20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीजों को 2.5 ग्राम थायरम अथवा 1.0 ग्राम कार्बेन्डाजिम साथ में 4-5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फफूंदनाशी से बीजोपचार के पश्चात् बीज को राइजोबियम एवं पी.एस.बी. कल्चर से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिये 25 ग्राम गुड़ तथा 20 ग्राम राइजोबियम एवं पी.एस.बी. कल्चर को 50 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 किलोग्राम बीज पर हल्के हाथ से मिलाना चाहिये एवं बीज को 1-2 घंटे छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई के लिये उपयोग करना चाहिये। मूंग की खेती हेतु कतार से कतार की दूरी 30 सेमी एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखी जाना उपयुक्त है।

उवज़्रक प्रबंधन

उवज़्रक का उपयोग कृषि प्रयोगशाला से मिट्टी जांच की सिफारिश के आधार पर करें। सामान्य रूप से मूंग की फ़सल में 15-20 किलोग्राम नत्रजन, 40-60 किलोग्राम स्फुर तथा 20-30 किलोग्राम पोटाश एवं 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें । सभी उर्वरकों को बुआई के समय डालना चाहिये।

खरपतवार प्रबंधन

सामान्यत: फसल की वृद्धि के साथ ही कई प्रकार के चौड़ी व संकरी पत्तियों वाले खरपतवार उग आते हैं, जो फसल को दिए गए पोषक तत्वों व पानी का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे मूंग की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु बुवाई से पूर्व लूक्लोरोलिन 1 किग्रा/हेक्टेयर की दर से छिडका़व करें। इसके अतिरिक्त पेंडीमिथालिन 0.75 किग्रा/हेक्टेयर की दर से छिडका़व फसल उगने से पूर्व कर खरपतवारों से छुटकारा पा सकते है। जायद की फसल में पहली सिंचाई के 20 से 30 दिन पश्चात् एक बार फसल की निराई-गुड़ाई करें।

6. जल प्रबंधन

जायद में हल्की भूमि में 4-5 बार सिंचाई की जबकि भारी भूमि में 4-5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शाखायें बनते समय तथा दाना भरते समय भूमि में नमी पर्याप्त रहे।

7. रोग प्रबंधन

मूंग में फफूंदजनित रोगों में चूणीज् कवक, मैक्रोफोमिना झुलसन, सरकोस्पोरा पर्ण दाग तथा एन्थ्रेक्नोज प्रमुख हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिये रोगरोधी किस्मों का चयन करें साथ ही उचित बीजोपचार करें । इसके अलावा बुआई के 30 दिन बाद फ़सल पर कार्बेन्डाजिम दवा की 600 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ावश्यकतानुसार 15 दिन बाद छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग में पीला मोजेक या पीली चितेरी रोग अधिक लगता है । यह एक विषाणुजनित रोग है जिसका एक पौधे से दूसरे पौधे में सं मण सफेद मक्खी द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिये रोगरोधी प्रजातियां लगायें। खेत में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रारंभ में कुछ ही रोगी पौधे होते है जिन्हें लक्षण दिखते ही उखाड़कर नष्ट कर दें और सफेद मक्खी की रोकथाम करें। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड की 150 मिली या डाइमिथिएट की 500 मिली प्रति हेक्टेयर मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें जरुरत पड़ने पर 12-15 दिन में छिड़काव दोहरायें।

8. कीट प्रबंधन

मूंग की फ़सल पर काटने वाले एवं रसचूसक दोनों प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। भेदक कीटों में पिस्सू भृंग, फ़्ली भेदक कीट तथा पत्ती मोड़क कीट प्रमुख हैं जिनके नियंत्रण के लिये प्रोफेनोफ़ॉस की 1 लीटर या क्लोरेन्ट्रानिलिट्रोल की 500 मिली या स्पाइनोसैड की 125 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से दो बार छिड़काव करें । रस चूसक कीटों जैसे सफेद मक्खी, थ्रिप्स या जैसिड्स के नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड की 150 मिली या डाइमिथोएट की 500 मिली प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करें। भेदक एवं रसचूसक दोनों प्रकार के कीटों का प्रकोप होने पर प्रोफेनोसाइपर दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है ।

9. कटाई पैदावार एवं भंडारण

जब मूंग की 85 प्रतिशत फ़लियां परिपक्व हो जायें तब फ़सल की कटाई करें। अधिक पकने पर फ़लियां चटक सकती हैं अतः कटाई समय पर किया जाना आवश्यक होता है। उन्नत तकनीकी अपना कर ग्रीष्मकालीन में मुंग की लगभग 10-12 कुंतल तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। कटाई उपरांत फ़सल को गहाई करके बीज को 9 प्रतिशत नमी तक सुखाकर भंडारण करें।

कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी एवं कृषकों को मिला सम्मान

शिवपुरी। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में म.प्र. शासन के ऊर्जा मंत्री एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्यु न सिंह तोमर की उपस्थिति के साथ जिले के गणमान्य अतिथियों एवं जिला कलेक्टर से जिले में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कृषकों के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी संस्था को भी स मानित किया गया।

शिवपुरी जिले में उन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकियों के साथ-साथ भारत सरकार एवं म.प्र. शासन की कृषि एवं संबंधित योजनाओं क वृहद हस्तांतरण के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र शिवुपरी को तथा विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कृषकों को जिनमें हल्की भूमि में आंवला आधारित कृषिवानिकी के लिए रामगोपाल गुप्ता ग्राम भौंती विकासखण्ड पिछोर, प्राकृतिक खेती की शुरूआत एवं प्रोत्साहन के लिए गोविंद दांगी कृषक ग्राम संगेश्वर विकासखण्ड कोलारस, फसल विविधता तथा नवाचार गतिविधियों के लिए कृषक धनीराम धाकड़ ग्राम पाटखेड़ा विकासखण्ड शिवपुरी एवं सीमांत कृषक तथा अमन लोधी ग्राम नयाखेड़ा विकासखण्ड पिछोर को कृषि तकनीकियों को सोशल मीडिया पर कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के समन्वय में प्रसारित कराने में सहयोग के लिए दिया गया।

विश्वद्यािलय कृषि छात्रों ने नये स्टार्टअप की संभावनाओं के लिए किया भ्रमण

जागत गांव हमार, शिवपुरी।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से बीएससी कृषि चतुर्थ वर्ष के छात्रों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के समन्वय में शिवपुरी जिले की फसल विविधता, जलवायु अनुकूलता एवं मृदा और मौसम की संभावनाओं के साथ-साथ जिले में चल रहे कृषि उद्यमों एवं नये स्टार्टअप शुरू होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर दुग्ध संघ के मिल्क चिलिंग प्लांट, सुदाना पशु आहार संयंत्र, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कृषि अभियांत्रिकी, बीज उत्पादन में जिले की अग्रणी संस्था हरदौल एग्रीकल्चर मार्के टिंग प्रोड्यूसर कंपनी, बीज एवं फार्म विकास निगम मनियर एवं प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों पर भी विगत दिनों भ्रमण किया। कृषि अभियांत्रिकी से कस्टम हायरिंग सेवाएं, बीज उत्पादन एवं स्वावलंबन, संतुलित पशु आहार निर्माण, दूध शीतगृह, भदावरी भैंस संरक्षण संवर्धन, भेड़ एवं बकरी का व्यावायिक पालन एवं उद्यमिता दृष्टिकोण से भ्रमण करते हुए वहां के विशेषज्ञों एवं प्रभारियों से विस्तार से जानकारी के साथ व्यावहारिक गतिविधियों को भी जाना जिससे कृषि छात्र आत्म निभज़्रता एवं नये स्टार्टअप की संभावनाएं भी तलाश करते हुए वोकल फॉर लोकल ब्राण्ड के साथ अपने शिक्षा ज्ञान को सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोग कर सकें।

शैक्षणिक ज्ञान के साथ किसानों से भी छात्रों ने प्राप्त किया अनुभव

कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के निर्देशन में यह भ्रमण केन्द्र के रावे कार्यक्रम प्रभारी डॉ. एमके भार्गव एवं सह रावे प्रभारी डॉ. नीरज कुमार कुशवाहा के समन्वय में जिले के विभिन्न संस्थाओं में कराया गया। भ्रमण एवं अध्ययन के दौरान है पको से लोकेन्द्र सिंह, मनीष त्यागी, मदन शर्मा, कृषि अभियांत्रिकी से भगवान सिंह नरवरिया, इंजीनियर अंकित सेन, दुग्ध संघ से सुनील शर्मा, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पडोरा से डॉ. एस. के. एस. धाकड़, उपसंचालक, पशु चिकित्सक डॉ. नितिन गुप्ता एवं अन्य संबंधित विशेषज्ञों की सहभागिता रही। कृषि छात्रों ने भी शैक्षणिक ज्ञान के साथ कृषि और कृषि से संबंधित विभागों एवं प्रगतिशील कृषकों के अनुभवों का लाभ लेते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया और अपने ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव एवं एग्रो इंडस्ट्री अटेचमेंट कायज् म को 24 जनवरी 2025 को पूणज् किया। इस अध्ययन एवं भ्रमण को शिवपुरी जिले में सफल और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बतलाया।

महिला कृषक सरस्वती वटके, यशोदा कासदे और अवधेष वर्मा को कृषक फेलो सम्मान 2024

बैतूल। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी महिला कृषक सरस्वती वटके, ग्राम खाखराढाना, तहसील घोड़ाडोंगरी को आदिवासी क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली के साथ पशुपालन, मुर्गीपालन, केंचुआ खाद उत्पादन, जैविक विधि द्वारा बागवानी तथा मशरूम उत्पादन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका का निर्वाहन करने पर, यशोदा कासदे, ग्राम दौड़ी तहसील शाहपुर को मोटे अनाज का जैविक विधि से उत्पादन, एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण कर उत्पाद का विक्रय करना, पशुपालन, मुर्गीपालन एवं केंचुआ खाद उत्पादन करने हेतु महिला कृषक फेलो सम्मान 2024 से सम्मानित किया। उक्त दोनों महिला कृषक राजकुमार सिरोरिया के सतपुड़ांचल एफपीओ से जुड़ कर कार्य कर रहे हैं। कृषक अवधेष वर्मा, ग्राम बैतूल बाजार, तहसील बैतूल को कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने, गन्ने से जैविक गुड़ उत्पादन करने, कृषि में जोखिम कम करने के उद्देष्य से डेयरी, बकरी एवं मुर्गीपालन, मसाला फसलों के बीज उत्पादन आदि कार्यों के लिए कृषक फेलो स मान 2024 से सम्मानित किया गया।

कपूरिया गांव में 16 एकड़ में कर रहे हैं जैविक खेती, स्वास्थ्यप्रद होने के साथ ही अच्छी कमाई भी

आकाश ने लगाई देशी गेहूं की 36 किस्में 15 हजार क्विंटल तक है कीमत

अनिल दुबे। जागत गांव हमार, सागर

मध्यप्रदेश के सागर जिले में मल्टीलेयर फार्मिंग के साथ देसी गेहूं की 36 किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है। लैब में जांच कराने के बाद एक एकड़ खेत में इन देसी किस्मों को लगाया गया है। किसान की मानें तो इन 36 किस्मों में 4 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल कीमत के गेहूं शामिल हैं। जिनकी उपज एक एकड़ में 12 क्विंटल से लेकर 22 क्विंटल तक होती है। साथ ही देसी गेहूं का आटा, दलिया समेत अन्य रेसिपी बनाकर सेवन करने से बीमारियों पर कंट्रोल होता है। लोग स्वस्थ रह सकते हैं। स्मार्ट किसान सीरीज में इस बार आपको सागर जिले के ग्राम कपूरिया में रहने वाले युवा किसान आकाश चौरसिया से मिलवाते हैं। इनका जिला मुख्यालय से करीब 8 किमी दूर स्थित कपूरिया गांव में करीब 16 एकड़ का फार्म है। जहां पर वह जैविक खेती करते हैं। वह मल्टीलेयर मार्फिंग के जनक भी माने जाते हैं। युवा किसान आकाश बताते हैं कि मैंने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है। 12वीं पास करने के बाद एमबीबीएस की तैयारी शुरू की, लेकिन कुछ दिनों में ही मन बदल गया। मैंने देखा कि इस समय लोग हाइब्रिड खाद्य सामग्री का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में मैं डॉक्टर बना तो लोगों की सेहत अच्छी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान के खान-पान से लोगों की सेहत और बिगड़ने वाली है। इसलिए सेहत सुधारने पर फोकस किया। खाना ही हमारी सेहत है। खाने से बीमारियां खत्म होंगी। इसलिए पढ़ाई छोड़कर जैविक खेती शुरू की।

गेहूं की देसी किस्म तलाशकर इन्हें लैब भेजा- आकाश ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की हाइब्रिड किस्मों का आटा, दलिया समेत अन्य रेसिपी का लोग सेवन कर रहे हैं। लेकिन इस गेहूं में शरीर के लिए पर्याप्त गुणकारी तत्व उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मैंने देसी गेहूं की किस्मों का संरक्षण कर उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिसके बाद गेहूं की देसी किस्मों का बीज तलाशा। 36 गेहूं की देसी किस्मों के बीज मिले। उन सभी बीजों की लैब में जांच कराई। जांच में उनके अंदर पाए जाने वाले गुणकारी तत्वों की जानकारी मिली। जिसके बाद उक्त किस्मों को खेत में लगाने का निर्णय लिया। वर्तमान में कपूरिया गांव के एक एकड़ खेत में 36 गेहूं की देसी किस्मों को लगाया है। जिनसे इनके बीज को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश समेत अन्य प्रदेश के किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा राजघाट रोड पर स्थित अपने खेत में भी देसी गेहूं की खेती कर रहा हूं।

15 हजार के खर्चे में कमा सकते हैं 1 लाख रुपए

किसान आकाश चौरसिया ने बताया कि यदि किसान सोना-मोती गेहूं की खेती करता है तो यह फायदेमंद होगा। सबसे पहले किसान को खेत तैयार करना होगा। इसके लिए 100 किलो चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर डालकर करीब 10 दिन तक खेत को खाली छोड़ें। खेत में नाइट्रोजन और बाकी तत्वों की पूर्ति के लिए दो टन प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फो कंपोस्ट और 5 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद डालने के बाद बीजोपचार कर सोना-मोती किस्म की बुआई करें। बुआई करने का समय 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। बुआई के बाद करीब 4 बार पानी देना होता है। करीब 140 दिन में फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस फसल की प्रति एकड़ उपज 18 से 22 क्विंटल तक होती है। किसान को एक एकड़ में करीब 15 हजार रुपए का खर्चा आता है। उपज के बाद वह एक एकड़ में करीब 1 लाख रुपए मुनाफा कमा सकता है।

90 से 140 दिन में तैयार होती है फसल

किसान ने बताया कि देसी गेहूं की 36 किस्मों की फसल अलग-अलग समय में पूरी तरह तैयार होती है। यह फसलें 90 दिन से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। साथ ही एक एकड़ में किसान को 12 से 22 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। जिसकी कीमत 4 हजार से लेकर 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक रहती है। ऐसे में यदि किसान देसी गेहूं लगाते हैं तो उन्हें अच्छा उत्पादन मिलने के साथ ही मुनाफा भी होगा।

खेत में बनाई अलग-अलग क्यारी

किसान आकाश चौरसिया ने अपने खेत में देसी गेहूं की 36 किस्मों को लगाया है। जिसमें सोनी-मोती गेहूं, काली मूंछ, बसंती,चावल काठी गेहूं, प्रताप, बंशी, कठिया, खपली, मालविका बसंती, हंसराज, खैरा, नीलांबर, गुलांबरी, काला गेहूं, 306, 307, 322, 315, लाल गेहूं, कुदरत, सर्जना, शरबती, श्री समेत अन्य गेहूं की किस्में लगाई हैं। इनके लिए खेत में अलग-अलग क्यारी बनाई गई हैं।

शुगर, गैस, माइग्रेन जैसी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

देसी गेहूं की किस्मों में पोषक तत्वों व गुणकारी तत्वों की मात्रा बेहद अच्छी है। किसान ने उनका लैब टेस्ट कराया है। जिसमें पता चला है कि देसी गेहूं की कई किस्मों में ग्लूटेन नहीं होता है। कुछ शुगर फ्री हैं। कुछ पेट संबंधी रोग ठीक करने में सक्षम हैं। किसान ने बताया कि देसी गेहूं के सेवन से शुगर, गैस, माइग्रेन समेत अन्य बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही लगातार सेवन करने से इन बीमारियों से छुटकारा भी मिल सकता है। क्योंकि देसी गेहूं जिंक, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम या आयरन जैसे तत्वों से जुड़े अच्छे गुण होते हैं।

जानिए...देसी गेहूं के किस्मों के फायदे

खपली गेहूं: बीज की मात्रा 60 किलो प्रति एकड़, पानी 3, उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़। बाजार मूल्य 8000 से 10,000 रुपए क्विंटल होती है। विशेष गुण- इसमें फाइबर और मिनरल्स अधिक होते हैं। साथ ही इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स तत्व कम होता है जो शूगर के मरीजों के लिए लाभकारी होता है।

चावल काठी गेहूं: बीज की मात्रा 70 से 80 किलो प्रति एकड़, पानी 3, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। बाजार मूल्य 9000 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें ग्लूटेन न के बराबर होता है जो कि कब्जियत के लिए बेहद लाभकारी होता है।

बंसी गेहूं: बीज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रति एकड़, पानी 3, उपज 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 7000 से 9000 प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें प्रोटीन अधिक होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तनाव के लिए लाभकारी होता है।

कठिया गेहूं: बीज की मात्रा 40 से 50 किलो प्रति एकड़, पानी 2, उपज 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़। बाजार मूल्य 6000 से 7000 प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन ए अधिक होता है जो शरीर के पोषण में अधिक लाभकारी है।

सोना मोती गेहूं: बीज की मात्रा 25 से 30 किलो प्रति एकड़, पानी 4, उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 10000 से 12-15000 रुपए प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें जिब्रालिक और फोलिक एसिड पाया जाता है और फाइबर भी अधिक होता है। यह शुगर और ह्रदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है।

- /□□□ »□ª□·: बीज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रति एकड़, पानी 4, उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन होता है जो हार्ट पेसेंटो के अधिक लाभकारी होता है।

नीलांबरी गेहूं: बीज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रति एकड़, पानी 4, उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 6000 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें एंथोसाइनीन पिगमेंट और फेनोलिक एसिड होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

सूर्या गेहूं: बीज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रति एकड़, पानी 3, उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 5000 से 6000 रुपए क्विंटल। विशेष गुण- इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह गेहूं हड्डी से संबंधित बीमारियों के लिए लाभकारी होता है।

प्रताप गेहूं: बीज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रति एकड़, पानी 4, उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार मूल्य 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल। विशेष गुण- इसमें विटामिन बी 5 और विटामिन बी 6 पाया जाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए

किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा

बोनस की जगह सीधा लाभ देने का फैसला

10 हजार रुपए खाते में डालेगी प्रदेश सरकार

» धान उत्पादक किसानों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि

» सीएम की घोषणा 2,000 रुपए हेक्टेयर मिलेगी राशि

» पांच हेक्टेयर तक सीमा, अधिकतम मिलेंगे दस हजार

जागत गांव हमार, भोपाल।

राज्य सरकार प्रदेश के धान उत्पादक सभी किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। यह प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपए रहेगी। कृषि विभाग इसके लिए योजना तैयार कर रहा है। इसमें पांच हेक्टेयर तक की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है। योजना को मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। राशि एक-दो माह में किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में एक बड़ा कार्यक्रम कर अंतरित की जाएगी।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 2,700 रुपये में गेहूं और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया। जब गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हुआ और बोनस की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बाद में सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया।

योजना में शामिल किए जाएंगे छोटी बड़ी जोत वाले सभी किसान

दिसंबर, 2024 में राज्य सरकार ने तय किया कि धान उत्पादक किसानों को बोनस देने के स्थान पर प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप योजना का प्रारूप तैयार किया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इसलिए इसके दायरे में लघु, सीमांत और बड़ी जोत वाले सभी किसान इसमें शामिल किए जाएंगे। हालांकि, इसमें अधिकतम सीमा रखी जाएगी यानी पांच हेक्टेयर तक किसानों को लाभ मिलेगा।

एमएसपी पर सरकार ने खरीदा 43 लाख 47 हजार 206 टन धान

प्रदेश में इस वर्ष किसानों ने 38.86 लाख हेक्टेयर में धान की बोवनी की थी। छह लाख 368 हजार 654 किसानों से 43 लाख 47 हजार 206 टन धान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है। बाजार में दाम कम होने के कारण बड़ी संख्या में किसानों ने उपज रोककर भी रखी है। इस वर्ष कितने किसानों ने धान की खेती की, यह जानकारी राजस्व विभाग से ली जा रही है। विभाग गिरदावरी करता है, जिसमें यह जानकारी रहती है कि किस किसान ने कितने क्षेत्र में किस फसल की खेती की है।

पोषक तत्वों से भरपूर, कई बड़े शहरों से आना शुरू हो हुई मांग

शराब नहीं, अब महुआ से बन रहे कुकीज

जागत गांव हमार, भोपाल।

आदिवासी बाहुल्य छिंदवाड़ा जिले में अब आदिवासी परिवार महुआ से शराब बनाने का काम छोड़कर उससे कुकीज बना रहे हैं। इससे उनकी आय भी बढ़ रही है, साथ ही पारंपरिक कुरीती से भी दूर हो रहे हैं। यह कुकीज खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होने से इनकी मांग अब बड़े शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि अब छिंदवाड़ा जिले की नई पहचान भी इस कुकीज से होना शुरू हो गई है। दरअसल जिले के छोटे से गांव राजाखोह की चार महिलाओं ने गांव को यह नई पहचान दिलाई है। इन महिलाओं ने तीन साल पहले समूह बनाकर महुआ के फूल से कुकीज बनाने का काम शुरू किया था। इन महिलाओं के उत्पाद जिले में ही नहीं प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों-नगरों में फेमस हो गए हैं। देश भर के लोग इस छोटे से गांव में महुआ वाले कुकीज के लिए आना शुरु हो गए हैं। इस गांव की देवकी चौरे, लता मर्सकोले, नीतू अहिरवार और मंजू चौरे सहित कुछ महिलाओं ने अन्यका महुआ उत्पादक समूह का गठन किया। इन महिलाओं ने 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करके आदिवासी जीवन शैली से जुड़े व्यंजनों को व्यवसायिक स्वरूप देने की योजना बनाई। इसी के तहत उन्होंने महुआ के फूल से कुकीज बनाने का फैसला किया और ये आईडिया हिट हो गया। महुआ के फूल में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। महुआ के फूल डायबिटीज के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। महुए में कई चिकित्सीय गुण होते हैं, जो शरीर को अलग-अलग प्रकार के स्वास्थ्य लाभ देते हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनी ने की मदद

गांव की महिलाओं का जज्बा देखकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने सीएसआर मद से इन महिलाओं को आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराईं। इसके पहले महिलाओं ने सात दिन की ट्रेनिंग भी दिलाई गई, जिसमें कुकीज बनाने का तरीका सीखा। उनके उत्पाद के लिए आसपास के 13 गांवों के ग्रामीणों से महुआ एकत्र कराया जाता है। इससे जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार मिला है। जिला स्तर पर लगने वाले कृषि मेला, वन मेला सहित अन्य आयोजनों में इस समूह के स्टॉल को आमंत्रित किया जाने लगा है। इनके द्वारा बनाए जा रहे महुआ के कुकीज की डिमांड अब दिल्ली, भोपाल, हरदा, जबलपुर, सूरत, मुंबई, नागपुर सहित दर्जनों शहरों में होने लगी है। इससे समूह का व्यापार भी बढ़ रहा है।

महुए में रोक दी जाती है एल्कोहॉल की प्रोसेस

अन्यका महुआ उत्पादक समूह द्वारा विशेष तरीके से महुआ बिस्किट व महुआ लड्डू बनाया जाता है। इन उत्पादों में प्रयोग होने वाला महुआ किण्वन विधि द्वारा नहीं गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इस महुए में एल्कोहॉल उत्पन्न नहीं होता। महुआ बिस्किट के अतिरिक्त कुटकी व मैदा के बिस्किट और बेकरी उत्पाद जैसे टोस्ट ब्रेड भी यहां बनाए जाते हैं।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- [illegible]iyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304

4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में मिशन सोयाबीन शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में सोयाबीन का उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल संचालित की जा रही है। धान की देशी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के कृषि विश्व विद्यालयों के माध्यम से धान की देशी फसलों का संरक्षण एवं उनसे नवीन किस्मों को विकसित किया जा रहा है। धान की जीरा शंकर, राजभोग, विष्णुभोग, चिन्नौर, कालीमूंछ जैसी किस्मों का संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी तरह गेहूँ की देशी किस्म का संरक्षण एवं उनसे नवीन किस्मों को विकसित किया जा रहा है। शरबती गेहूँ जैसी किस्मों का संरक्षण एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरसों विशिष्ट एफपीओ स्थापित कर सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरसों के मुख्य उत्पादन वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में सरसों खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)